



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 623]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 नवम्बर 2017—कार्तिक 30, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2017

अधि. क्र. 87-एफ-1-30-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख, 292 ग एवं 292-ड के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख, 339-ग एवं 339-ड के साथ पठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15 क में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अवैध कालोनियां, जो निजी स्वामित्व की भूमि (शासकीय भूमि तथा विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि पर निर्मित नहीं हों) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक अस्तित्व में आ चुकी हों, को निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए नियमितीकरण किया जाएगा.”.

Not. No. 87-F-1-30-2011-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Sections 292-A, 292-B, 292-C and 292-E read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 339-A, 339-B, 339-C and 339-E read with Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities

Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Nagarpalika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1998, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 15A, for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

- “(1) “Notwithstanding anything contained in these rules, the illegal colonies that came into existence upto 31st December, 2016 on private ownership land (not constructed on Government land and Development Authority ownership land) shall be regularized subject to the following conditions.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, उपसचिव.